कानपुर, बुधवार, 27 मई, 2026
वर्ष: 03, अंक: 130, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड यूपी में शुरू होगा 'वन डे गवर्नेंस' ...>Pg10

इरफान सोलंकी पर रंगदारी का आरोप ..>Pg03

मूल्य: 2 ₹

चुनाव आयोग के अधिकार बरकरार

SIR पर 'सुप्रीम' मुहर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश की चुनावी व्यवस्था और मतदाता सूची की पारदर्शिता से जुड़े बहुचर्चित 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्क्रुक्र प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना और अपात्र नामों को हटाना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि केवल इसलिए किसी प्रक्रिया को गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता कि वह सामान्य पुनरीक्षण प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 से प्राप्त है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का अर्थ किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होना नहीं है। नागरिकता तय करने का अधिकार केवल सक्षम प्राधिकारी के पास रहेगा।

यह मामला तब चर्चा में आया था जब चुनाव आयोग ने जून 2025 में बिहार से 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' अभियान शुरू किया था। बाद में इसे पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया। इस प्रक्रिया के तहत उन मतदाताओं से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए जिनके नाम वर्ष 2002 या 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं थे। आयोग का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अधिक शुद्ध बनाना बताया गया।

याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज , चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव और कई राजनीतिक नेताओं ने दलील दी थी कि स्क्रुक्रप्रक्रिया संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उनका कहना था कि यह एक प्रकार का छिपा हुआ एनआरसी है, जिसमें गरीब, प्रवासी और वंचित वर्गों को पुराने दस्तावेज न होने के कारण मतदान अधिकार से वंचित किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच नहीं कर सकता।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि सत्यापन के दौरान आधार कार्ड समेत अन्य मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएं ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो। जनवरी 2026 में फैसला सुरक्षित रखने के बाद मंगलवार को अदालत ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया।

निर्वाचन आयोग ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने वाला निर्णय है। आयोग के अनुसार, देशभर में फर्जी, मृत और दोहरे मतदाताओं की पहचान कर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। दूसरी ओर विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने आशंका जताई कि भविष्य में इस प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर भी असर डालेगा।

आखिर क्यों जरूरी माना गया एसआईआर?

मतदाता सूची में वर्षों से मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों की शिकायतें उठती रही हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि स्क्रुक्रका मकसद सूची को पूरी तरह अपडेट और पारदर्शी बनाना है, ताकि केवल पात्र नागरिक ही मतदान कर सकें।

विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता

विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का तर्क है कि गरीब, प्रवासी मजदूर और ग्रामीण आबादी के पास पुराने दस्तावेज नहीं होते। ऐसे में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या सीमा तय की?

अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग केवल मतदाता सूची का सत्यापन कर सकता है। किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना या उसे विदेशी घोषित करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

आने वाले चुनावों पर असर

विशेषज्ञ मानते हैं कि फैसले के बाद कई राज्यों में व्यापक स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल सकते हैं। इससे चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन और मतदाता सत्यापन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव संभव है।

मौत की रफ्तार: गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रॉली में घुसी स्कॉर्पियो 3 की मौत

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

रायबरेली। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में किशोरी समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली से जौनपुर लौट रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।

➪ दिल्ली से जौनपुर लौट रहा था परिवार, मासूम समेत पांच घायल अस्पताल में भर्ती

हादसा सलोन कोतवाली क्षेत्र के मीरजहांपुर के पास रात करीब साढ़े दस बजे हुआ। धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मंजर बेहद भयावह था। सड़क पर कांच के टुकड़े, बैग, कपड़े और मोबाइल बिखरे पड़े थे, जबकि वाहन के अंदर फंसे लोग दर्द से कराह रहे थे।

स्थानीय लोगों ने पुलिस पहुंचने से पहले ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। किसी ने वाहन के दरवाजे खींचे तो किसी ने मोबाइल की रोशनी में अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला जा सका।

जानकारी के मुताबिक जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र स्थित मानिकपुर गांव निवासी एक ही परिवार के आठ लोग दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। हादसे में 12 वर्षीय समृद्धि, 55 वर्षीय सरोज सिंह और 22 वर्षीय संगीता सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं प्रतिभा सिंह, सविता सिंह, गुरुचरण सिंह, नीरज सिंह और तीन वर्षीय समर्थ सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। मासूम समर्थ की हालत गंभीर होने पर उसे एम्स रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों को प्रतापगढ़ और रायबरेली के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सलोन कोतवाल बालेन्दु गौतम ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और पांच घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सिख युवक से मारपीट मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, समझौते का दबाव बनाने का आरोप

देर रात आरोप हैं कि सिख युवक को पीटा गया था

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सिविल लाइंस क्षेत्र में सिख युवक की पगड़ी उतारकर मारपीट करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है और अज्ञात नंबरों से धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार आजादनगर निवासी सहज भाटिया का छोटा भाई वंश 22 मई को सिविल लाइंस स्थित एक स्टूडियो बार गया था।

आरोप है कि वहां लिफ्ट में पहले से मौजूद पांडुनगर निवासी धैर्य गुप्ता अपने साथियों और एक युवती के साथ था। किसी बात को लेकर विवाद होने पर गाली-गलौज शुरू हो गई और बाद में मारपीट की गई।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने वंश की पगड़ी उतार दी, बाल खींचे और सिर

दीवार से भिड़ा दिया। घटना के बाद वंश की मां सोनिया भाटिया ने कोतवाली थाने में धैर्य गुप्ता समेत तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में आरोपी धैर्य गुप्ता और ओम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है। वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि वंश पुराना परिचित है और घटना के समय नशे की हालत में था, जिसके बाद विवाद बढ़ा।पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। होटल संचालक कमल भाटिया का कहना है कि दो पक्षों में विवाद नीचे ग्राउंड एरिया में हुआ था, मेरे होटल से कोई लेना-देना नहीं है.

ज्येष्ठ माह के चतुर्थ मंगलवार पर रामेष्ट धाम में गूंजा सुंदरकांड पाठ

» स्वराज इंडिया -संवाददाता

कानपुर। ज्येष्ठ माह के चतुर्थ मंगलवार के अवसर पर केशव नगर स्थित रामेष्ट धाम, केशव मधुवन वाटिका में भक्ति और श्रद्धा के वातावरण के बीच सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर भगवान श्रीराम और हनुमान जी की आराधना की।

कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के विशेष श्रृंगार से हुई। मंदिर में भगवान को नए वस्त्र, मुकुट और पुष्प मालाएं अर्पित की गईं। चंदन, धूप और अगरबत्ती की सुगंध से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया।सुंदरकांड पाठ के उपरांत भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तजन भक्ति रस में डूबे नजर आए। धार्मिक आयोजन के अंत में आरती कर प्रसाद वितरण किया गया।

समिति के महासचिव राजेंद्र अवस्थी ने बताया कि ज्येष्ठ माह में मंगलवार का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना और सुंदरकांड पाठ से सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना की जाती है।कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजेश्वरी दुबे, रेनू अवस्थी, बेबी शुक्ला, मोहिनी बाजपेई, जयंती बाजपेई, पिंकी त्रिवेदी, बीना, किरण, सुषमा, रेखा दीक्षित, मीरा, जयराम दुबे, श्याम बिहारी शर्मा, पी.के. त्रिपाठी, योगेश दीक्षित, बी.के. तिवारी एवं राम प्रकाश पाण्डेय सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

औद्योगिक क्षेत्रों में शांति के लिए एडीजी की हाई पावर बैठक

» बैठक में कानपुर रेंज के डीआईजी हरीश चन्दर, कानपुर देहात के डीएम कपिल सिंह, एसपी श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय मौजूद रहीं

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से कानपुर जोन कार्यालय में एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में हाई-पावर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानपुर रेंज के डीआईजी हरीश चन्दर, कानपुर देहात के डीएम कपिल सिंह, एसपी श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय, सीओ संजय गुप्ता समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।बैठक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, श्रमिकों और प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की रणनीति तैयार करना रहा।

एडीजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक गतिविधियों और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सतर्कता के साथ कार्य किया जाए।उन्होंने कहा कि श्रमिक आंदोलनों अथवा विवादों के दौरान संवाद, संवेदनशीलता और संयम के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

साथ ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।एडीजी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रमिक आंदोलनों से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जाए तथा अफवाह फैलाने वाले और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए प्रभावी रणनीति पर भी चर्चा की गई।

पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर रंगदारी का आरोप, बकरा मंडी में बवाल

पूर्व विधायक बोले- वसूली की शिकायत पर पहुंचे थे, लगाए गए आरोप बेबुनियाद

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। चमनगंज स्थित हलीम ग्राउंड में लगने वाली बकरा मंडी मंगलवार रात उस समय विवाद और हंगामे का केंद्र बन गई, जब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके गनर पर रंगदारी मांगने, मारपीट और रुपए लूटने के आरोप लगे। घटना के बाद मंडी से जुड़े व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर जुट गए और मंडी के सभी गेट बंद कर पूर्व विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

पटकापुर निवासी वफा अब्बास ने आरोप लगाया कि वह कई वर्षों से हलीम ग्राउंड में बकरा बाजार का संचालन करते आ रहे हैं। ईद-उल-अजहा को लेकर बाजार में मंगलवार रात भारी भीड़ थी। इसी दौरान पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपने साथियों और गनर के साथ वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर उनके गनर व साथियों ने मारपीट की। पीड़ित का दावा है कि मंडी संचालन के नाम पर तीन लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। विरोध करने पर उनके पास मौजूद करीब 2.70 लाख रुपए छीन लिए गए।

घटना की जानकारी फैलते ही व्यापारियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। हलीम ग्राउंड के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने पूर्व विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थिति बिगड़ती देख चमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि प्रदर्शनकारी आरोपियों पर तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे।

करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बाद बकरा मंडी पदाधिकारियों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई, जिसमें लूट, रंगदारी और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि हलीम ग्राउंड में वर्षों से लगने वाली बकरा मंडी में कारोबारियों और ग्राहकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। इसी सूचना पर वह विधायक नसीम सोलंकी के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वसूली का विरोध करने पर कुछ लोगों ने उनके सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की और कार्बाइन छीनने का प्रयास भी किया।

⇨ हलीम ग्राउंड में व्यापारियों का हंगामा, गेट बंद कर लगाए मुर्दाबाद के नारे

इंटर पास युवक बना 'आरबीआई अफसर' बनकर जेई से 95 लाख की ठगी

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां इंटर पास युवक ने खुद को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बताकर पुलिस आवास विकास निर्माण निगम के एक जेई से 95 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी ने यह रकम पिछले नौ वर्षों में अपने और पत्नी के खातों में ट्रांसफर कराई। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

⇨ गूगल पर नंबर खोजते ही साइबर जाल में फंसे रिटायर्ड जेई, 9 साल तक चलता रहा खेल

डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शारदानगर निवासी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव पुलिस आवास निर्माण निगम में जेई थे। उन्होंने 28 बीमा पॉलिसियां ले रखी थीं, जिनमें से 22 किस्त जमा न होने के कारण लैप्स हो गई थीं। वर्ष 2017 में पॉलिसी का पैसा रिफंड कराने के लिए उन्होंने गूगल पर नंबर सर्च किया, जहां वे आरबीआई की फिशिंग वेबसाइट पर पहुंच गए।

बताया गया कि वेबसाइट पर मिले नंबर पर फोन करने पर सामने वाले ने खुद को आरबीआई का जनरल मैनेजर बताया और व्हाट्सएप पर रिजर्व बैंक का फर्जी नोटिस भेज दिया। इसके बाद लैप्स पॉलिसी दोबारा शुरू कराने और रिफंड दिलाने के नाम पर अलग-अलग बहाने बनाकर 95 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। साल 2022 में जेई रिटायर भी हो गए, लेकिन लंबे समय तक रकम देने के बावजूद उन्हें पॉलिसी का पैसा वापस नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने नजीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान सेंट्रल जोन साइबर सेल और स्वाट टीम ने मामले की परतें खोलनी शुरू कीं। पुलिस ने पीड़ित की मदद से आरोपी को नकद पैसे देने के बहाने जेके मंदिर नहरिया के पास बुलाया, जहां से नजीराबाद पुलिस ने आरोपी दीपक सिंह और उसकी पत्नी आंचल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुल्तानपुर जिले के अलीमुद्दीनपुर गिधौना गांव के निवासी हैं। जांच में सामने आया कि दीपक इंटर पास है, जबकि उसकी पत्नी आंचल ने जीएनएम का कोर्स किया है। पुलिस के मुताबिक ठगी के 15 लाख रुपये आंचल के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, जबकि बाकी रकम दीपक ने अपने खाते में रखी।

पूछताछ में आरोपी दीपक ने बताया कि उसने कोई वेबसाइट नहीं बनाई थी। रिटायर्ड जेई ने खुद उसे फोन किया था। उसने खुद को आरबीआई मैनेजर बताकर बातचीत शुरू की और इलाज के लिए पैसों की जरूरत का हवाला देते हुए धीरे-धीरे ठगी करता रहा। आरोपी ने यह भी कबूल किया कि पत्नी को वह कहता था कि दोस्त इलाज के लिए पैसा भेज रहे हैं।

शूटिंग में एक्टर अजय त्रिपाठी की भूमिका जबर्दस्त

कानपुर में 'अंधा सिस्टम' शॉर्ट फिल्म की शूटिंग चर्चा में, भ्रष्ट व्यवस्था पर आधारित है कहानी

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में इन दिनों शॉर्ट फिल्म 'अंधा सिस्टम' की शूटिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह से कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही इस फिल्म की शूटिंग ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। फिल्म की कहानी समाज में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था और सिस्टम की खामियों पर आधारित है।

फिल्म के लेखक एवं निर्देशक दीपक यादव ने बताया कि फिल्म का नाम 'अंधा सिस्टम' केवल शीर्षक नहीं, बल्कि वर्तमान व्यवस्था पर एक तीखा प्रहार है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक 7-8 वर्ष का बच्चा समाज में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय को देखकर अपने ही मंत्री दादा के खिलाफ आवाज उठाता है।

फिल्म की शूटिंग कानपुर के यशोदा नगर, बिठूर, गंगा बैराज और स्वरूप नगर सहित कई प्रमुख स्थानों पर की गई है। फिल्म में मंत्री की भूमिका अजय त्रिपाठी ने निभाई है, जबकि बड़े उद्योगपति के किरदार में अरविंद यादव नजर आएंगे।

फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर विपिन आर पांडे हैं, जबकि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी की जिम्मेदारी संदीप तिवारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा शिवमोहन द्विवेदी, अरुण यादव, विकास राय, अमन भट्ट और अनिल त्रिपाठी ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।

फिल्म की सामाजिक विषयवस्तु और कानपुर की लोकेशनों पर हो रही शूटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह फिल्म समाज को एक मजबूत संदेश देने का काम करेगी।

सनिगवां में केडीए का बड़ा बुलडोजर एक्शन

31 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

71.5 बीघा क्षेत्र में चल रही अवैध प्लाटिंग को नोटिस, आगे होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

केडीए में नायक हैं डॉ रवि प्रताप सिंह

केडीए के चर्चित और तेज-तर्रार पीसीएस अधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह की कार्यशैली ने अधिकारियों और जनता का ध्यान आकर्षित किया है. इन्होंने अब तक हजारों बीघा में प्लॉट माफियाओं पर कार्रवाई की है .

उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी प्लाटिंग में जमीन खरीदने से पहले उसकी ले-आउट स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें और प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही निर्माण कार्य करें, ताकि भविष्य में आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

» प्रमुख संवाददाता न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए जोन-4 क्षेत्र में करीब 31 बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की। यह अभियान उपाध्यक्ष अंकुर कौषिक और सचिव अभय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलाया गया।प्राधिकरण की टीम ने सनिगवां स्थित आदर्श विहार सोसाइटी में अजब सिंह, सुरेन्द्र कुशवाहा, हिमांशु व अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति कराए विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की। लगभग 3 घंटे चले अभियान में 2 जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, नाले, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट, सीवर लाइन तथा कई निर्माणाधीन एवं निर्मित भवनों को ध्वस्त कर दिया गया।इसके अलावा केडीए ने अहिरवां और नगवां क्षेत्र में विकसित की जा रही 4 अन्य अवैध प्लाटिंग को भी चिन्हित किया है। इनका निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।प्राधिकरण के अनुसार मौजा अहिरवां में करीब 2 बीघा, 32 बीघा और 35 बीघा क्षेत्रफल में तथा मौजा नगवां में करीब 2.5 बीघा क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के प्लाटिंग कार्य किया जा रहा था। इन सभी मामलों में नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता अटल चतुर्वेदी, सुपरवाइजर मनोज कुमार, संदीप यादव, आबिद अहमद, प्रमोद कुमार, अजय चैरसिया, शिवकुमार और उत्कर्ष कटियार समेत संबंधित थाने का पुलिस बल मौजूद रहा।

बाल श्रम कानून पर गोष्ठी में व्यापारियों को दी गई कानूनी जानकारी

बाल श्रम कराने पर 2 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माने की चेतावनी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

शास्त्री नगर स्थित केएस पैलेस गेस्ट हाउस में मंगलवार को बाल श्रम कानून को लेकर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शास्त्री नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र जायसवाल ने क्षेत्रीय पार्षद विनोद गुप्ता तथा श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर किया। गोष्ठी में दुकानदारों और व्यापारियों को बाल श्रम से जुड़े कानूनों और दंडात्मक प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना कानूनन अपराध है। वहीं 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाओं में काम पर लगाने पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा, 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

गोष्ठी में लोगों से अपील की गई कि यदि आसपास किसी नाबालिग बच्चे का शोषण होता दिखे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें। कार्यक्रम में संजीव खत्री, वेद शुक्ला, जेपी यादव, कालीचरण वर्मा, अजय वर्मा, मोनू श्रीवास्तव, पवन जग्गी, पंकज वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, अमित मिश्रा और सूर्यभान सहित कई लोग मौजूद रहे

भीषण गर्मी के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज, 29 मई से बारिश के आसार

» कानपुर में अगले तीन दिन लू का प्रकोप जारी रहने की चेतावनी,

» महीने के अंत में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बुलेटिन के अनुसार कानपुर मंडल में फिलहाल भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा।

मंगलवार को अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आगामी तीन दिनों तक आसमान साफ रहने के कारण लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों को दिन के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अधिकतम आर्द्रता 40 प्रतिशत और न्यूनतम 18 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि हवा की औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हवाएं उत्तर-पश्चिम दिशा से चलीं।

पूर्वानुमान के अनुसार 29 से 31 मई के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आसमान में मध्यम से घने बादल छाने, तेज हवाएं चलने तथा गरज-चमक के साथ स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को फसल प्रबंधन और सिंचाई कार्य मौसम को ध्यान में रखकर करने की सलाह दी है। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के नोडल अधिकारी एवं कृषि मौसम तकनीकी अधिकारी, सस्य विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई।

सम्पादकीय

क्रीमी लेयर को अलग करने की पहल

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करने से एक महत्वपूर्ण तार्किक चर्चा फिर से प्रारंभ हो गई है। जिसका मकसद है कि कैसे सकारात्मक पहल करके आरक्षण के उद्देश्य को अधिक न्यायसंगत, लक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। वास्तव में उनकी पहल का मकसद संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने का नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कि अनुसूचित जाति समुदाय के सबसे गरीब, सामाजिक रूप से सबसे अधिक वंचित और आरक्षण के लाभ में सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग को लाभ पहुंचाने का मकसद पूरा करना। बहुत संभव है कि मुख्य न्यायाधीश के इस विचार से असहमति के तर्क दिये जाएं। वास्तव में, देश में दशकों से आरक्षण की बहस कोटा बढ़ाने पर केंद्रित रही है, लेकिन उनके न्यायसंगत वितरण की दिशा में पर्याप्त पहल नहीं हो पायी है। निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे, अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक-सामाजिक स्थिति वाले वर्ग ने ही बार-बार शिक्षा और सरकारी रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया है। वहीं दूसरी ओर पीढ़ी दर पीढ़ी अभावों के भंवर-जाल में फंसे परिवार- मसलन श्रमिक, सफाई कर्मचारी, भूमिहीन मजदूर परिवार लगातार हाशिये पर ही बने हुए हैं। यदि आरक्षण का मूल उद्देश्य संरचनात्मक असंतुलन को ही ठीक करना है तो इसके लाभ सीमित दायरे के लोगों को ही नहीं मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ओबीसी वर्ग के लिये यह प्रावधान सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इसमें दो राय नहीं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत आरक्षण लाभ में इस तरह के एकाधिकार को रोकने का एक सशक्त साधन है। इस प्रावधान का वंचित अनुसूचित जातियों तक विस्तार करना एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करता है कि सामाजिक गतिशीलता, हालांकि सीमित स्तर पर कुछ ही लोगों के लिये संभव हुई है। साथ ही अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिये नीति को अनुकूलित किया जाना वक्त की जरूरत है।वास्तव में वर्तमान स्थिति आरक्षण के न्यायसंगत लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने में तार्किक नजर नहीं आती। जब किसी आईएएस अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी का बच्चा सामाजिक रूप से हाशिये पर गए वर्ग के किसी व्यक्ति के मुकाबले समान लाभों का दावा करना जारी रखता है तो इससे लक्षित उद्देश्य कमजोर हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रीमी लेयर को बाहर करने पर उनके जातिगत भेदभाव होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

लेकिन यह केवल यही दर्शाता है कि किसी भी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूह के भीतर, वंचितता की स्थिति अलग-अलग होती है। निश्चित रूप से स्पष्ट मानदंड, सामाजिक पिछड़ेपन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और दुरुपयोग को रोकने के लिये कारगर सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की टिप्पणी इस बात की ही परिचायक है कि सामाजिक न्याय का विस्तार होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के आरक्षण से क्रीमी लेयर को सोच-समझकर बाहर करने से समानता के संवैधानिक वायदे की पुष्टि हो सकती है।

इस पहल के विरोध में यह तर्क दिया जा सकता है यदि अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के उपवर्गीकरण को मान्यता दी जाती है, तो पहले इससे लाभान्वित लोगों को सुरक्षा कवच न मिल सकेगा।

बेटी पढ़ा तो लो मगर बचाएं कैसे

के.एस तोमर

क्या बेटी पालने में बेटे पालने के मुकाबले, कम संसाधन खर्च होते हैं। इन दिनों जब शहरी परिवारमात्र एक-दो बच्चों तक ही सीमित हैं, तब बेटियों की शिक्षा-दीक्षा पर भी बेटे की तरह ही खर्च होता है, लेकिन अब भी वे दोयम दर्जे की नागरिक हैं। नारा लगाते रहिए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। पिछले दिनों से त्विशा शर्मा का केस चर्चा में है। एक दिन में ही अखबारों के कुछ शीर्षक देखिए–संदिग्ध हालत में महिला की मौत।

त्विशा-दीपिका की मौत ने दिखाया आईना। विनोद नगर में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत आदि-आदि। ऐसी खबरें रोज आती हैं। एक महिला कमांडो तक की पीट-पीटकर हत्या की जा चुकी है। एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों की मानें, तो दहेज हत्या के मामलों में दिल्ली सबसे आगे फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक का नम्बर है।पिछले कुछ सालों से तो लगता था कि अब देश में बहुत बदलाव हो गया है। शादियां समानता के आधार पर हो रही हैं। इसका बड़ा कारण लगता कि चूंकि लड़कियां पढ़-लिख गई हैं, तो वे स्वयं भी ऐसे युवकों से विवाह करने से मना कर देती हैं, जिनके परिवार उन्हें अपने अनुकूल नहीं लगते। ऐसे बहुत से विवाह होते भी देखे हैं। आसपास ऐसे कई परिवार भी रहते हैं, जहां लड़कियां विवाह के बाद संयुक्त परिवारों में रहती हैं, कोई लड़ाई-झगड़ा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अब सोचती हूं कि जो दिखता है, वही सच नहीं होता। उसके पीछे भी बहुत कुछ छिपा रहता है।अक्सर हम मध्यवर्ग के लोग हर बात अशिक्षा से जोड़ देते हैं कि फलां ने ऐसा इसलिए किया होगा कि परिवार शिक्षित नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन त्विशा के मामले पर नजर डालें, तो उसके ससुराल में सब पढ़े-लिखे थे। सास रिटायर्ड जज, पति आपराधिक मामलों का वकील। फिर भी जब इस लड़की ने आत्महत्या कर ली, तो इसकी पहली सूचना उसके परिवार वालों को नहीं दी गई, बल्कि सास अपने जान-पहचान वालों से बातचीत करती रही। छियालीस फोन किए गए। एम्बुलेंस और पुलिस को फोन नहीं किया गया। यही नहीं सास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए, वे, वे ही थे जिन्हें आम तौर पर लड़कियों के चरित्र हनन के लिए लगाया जाता है। जैसे कि वह ड्रग एडिक्ट थी। एक दिन के लिए घर से बाहर चली गई थी। उसने गर्भपात करा लिया था। वह खाना नहीं बनाती थी। पौधों को पानी नहीं देती थी। शादी से पहले हमारे घर भी आई थी। ऐसे कौन अपने होने वाले ससुराल में आता है। वह अस्सी किलो की थी। उसे सीढ़ियों से उतारना कितना मुश्किल था। मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह गोल्ड डिगर यानी कि पैसे की लालची थी। उसने मुझे दादी होने का सुख नहीं दिया।ये बातें कोई ग्रामीण स्त्री नहीं कह रही है, एक रिटायर्ड जज कह रही है। सोचिए कि यदि इनके कोर्ट में ऐसे मुकदमे आते होंगे, तो इनका निर्णय क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत से निर्णय कहते हैं कि स्त्री अगर बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, तो उसके फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। शरीर उसका है, उस पर उसी का अधिकार है। यह भी कि आप पत्नी लाते हैं, कोई मेड नहीं कि खाना न बनाना तलाक का कारण बन सके। त्विशा पैसे कमाती थी। नोएडा से भोपाल जाने पर उसके बहुत से काम छूट गए थे। इस पर भी उसे ताने सुनने पड़ते थे। यानी कि एक स्त्री पैसे कमाए, उसे अपने पति के परिवार को सौंप दे। घर का काम करे। खाना बनाए। सबकी सेवा करे। किसी और से कभी बातचीत तक न करे, नहीं तो उसके चरित्र पर सवाल उठाने का अधिकार, हर ऐरे-गैरे नत्थू खैरे को मिल जाएगा। कई वकीलों ने कहा भी कि ये आरोप तो स्त्रियों पर सदा से लगते आए हैं। इन दिनों ऐसे वीडियोज और रील्स की भरमार है, जिनमें ऐसा न करने पर पत्नी को पति घर से निकालने और तलाक की धमकी देते पाए जाते हैं। एक तरफ तो ये वीडियोज समाज में फैली असलियत को बताते हैं, मगर दूसरी तरफ बहुत से लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करते होंगे। आखिर लड़कियां ही क्यों घर से निकाली जाएं।

अदालती फैसले में खेल संघों के लिए सबक

चयन ट्रायल से महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मामले में हाईकोर्ट ने अपने हालिया निर्णय से न केवल देश की एक खिलाड़ी के साथ हुए अन्याय का उचित संज्ञान लिया अपितु मातृत्व का सम्मान किया है। इससे भारतीय कुश्ती संघ की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा है।

एशियाई खेलों के लिए कुश्ती दल के चयन ट्रायल से महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मनमाने निर्णय पर उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती संघ को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि हमारे देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है। लेकिन भारतीय कुश्ती संघ ने तो विनेश फोगाट के मामले में अपने पुराने मानदंडों को ही बदल दिया (संभवतः व्यक्तिगत विद्वेष के चलते)। बता दें कि विनेश फोगाट ने अपनी खेल प्रतिभा से ?अनेक अवसरों पर भारतीयों का सिर ऊंचा किया है। हाईकोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक निर्णय से न केवल देश की इस महान खिलाड़ी के साथ हुए अन्याय का उचित संज्ञान लिया अपितु मातृत्व का सम्मान किया है और भारतीय कुश्ती संघ की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया है। इस निर्णय के चलते भविष्य में अन्य खेल महासंघों को भी खिलाड़ियों के प्रति अन्याय करने से रोकेगा।उल्लेखनीय है कि विनेश देश के लिए महिला कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सर्वाधिक पदक विजेता और ओलंपिक फ़ाइनल तक पहुंचने वाली देश की एकमात्र महिला पहलवान हैं। विनेश मां बनने के बाद कुश्ती में वापसी करना चाहती थी लेकिन उसे कुश्ती संघ के नियमों के नाम पर राष्ट्रमंडलीय व एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने से रोक कर दिया गया था। कई देशों में मां बनने के बाद खेलों में लौटने की इच्छुक महिला खिलाड़ियों के लिए नियमों में छूट दी गई और उन्होंने पदक जीतकर इसे सही सिद्ध किया। लेकिन विनेश की वापसी का रास्ता बंद कर दिया गया था। विनेश के साथ-साथ

देश के लाखों कुश्ती प्रेमियों के लिए यह निराशा की बात थी।विनेश की अद्वितीय खेल उपलब्धियां भारतीय कुश्ती के लिए गर्व की बात है। विनेश ने साल 2013 में एशियाई चैंपियनशिप से पदक जीतने का सिलसिला शुरू किया। इसके साथ ही जुझारू खिलाड़ी विनेश 2022 की विश्व चैम्पियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों तक लगातार दस वर्षों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए सर्वाधिक पदक (10 स्वर्ण पदकों सहित कुल 22 पदक) जीतने में सफल रहीं। महिला पहलवान विनेश विश्व चैंपियनशिप में दो पदक, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण सहित दो पदक और राष्ट्रमंडलीय खेलों में लगातार तीन स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की एकमात्र महिला पहलवान हैं। एशियाई चैंपियनशिप में एक स्वर्ण , तीन रजत और चार कांस्य पदकों के साथ आठ पदक जीतने वाली देश की एकमात्र पहलवान विनेश ने भारतीय कुश्ती का परचम विश्व स्तर पर फहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके दमख़म और कुश्ती के प्रति अद्भुत समर्पण के विश्व भर के खेल विशेषज्ञ और खेलप्रेमी क़ायल रहे हैं। अपनी खेल प्रतिभा और उपलब्धियों के कारण विनेश को अर्जुन पुरस्कार (2016), पद्मश्री (2018) और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (2020) व लॉरियस स्पोर्ट्स वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 2022 और 2024 में उन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन घोषित किया गया।विनेश ने तीन ओलंपिक खेलों में महिला कुश्ती में देश का प्रतिनिधित्व किया। साल 2024 के पेरिस ओलंपिक खेलों में पचास किलो भार वर्ग में वह फ़ाइनल तक पहुंची। फ़ाइनल मुकाबले से पूर्व जांच में कुछ अधिक वज़न पाए जाने पर उसे अयोग्य ठहरा दिया गया। उस निराशा के चलते विनेश ने संन्यास की घोषणा कर दी थी।हरियाणा के विधानसभा चुनावों में विधायक चुने जाने और मातृत्व ग्रहण करने के बाद एक बार फिर विनेश ने कुश्ती की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की ठानी। वह एक बार पुनः देश के लिए पदक जीतने की लालसा लिए हुए एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल में भाग लेने पहुंची थी लेकिन नियमों के नाम पर उसे भाग लेने से वंचित कर पुनः निराशा में धकेल दिया गया। विडंबना यह रही कि इस बार ओलंपिक समिति ने नहीं अपितु अपने ही देश के कुश्ती संघ ने उसके साथ न्याय नहीं किया था। कथित तौर पर ट्रायल का अवसर न दिये जाने के लिए नियम बदले जाने सहित सारी व्यूह रचना की गयी थी। शायद विनेश द्वारा गत वर्षों में महिला पहलवानों की न्याय संगत मांगों के लिए किए गए संघर्ष की यह परिणति थी।

..तो क्या अधूरा ही रह जाएगा सपना का 'सपना'

गोगूमऊ के मजदूर सुनील कठेरिया की बेटी सपना का कैमरे के सामने छलका दर्द

स्वराज इंडिया फालोअप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। चौबेपुर ब्लॉक के गोगूमऊ गांव में रहने वाले मजदूर सुनील कठेरिया का परिवार आज भी गरीबी, बीमारी और सरकारी उपेक्षा के बीच जिंदगी काटने को मजबूर है। परिवार की सबसे बड़ी पीड़ा सिर्फ कच्चा घर, शौचालय और बिजली की कमी नहीं, बल्कि उनकी बेटी सपना कठेरिया की अधूरी पढ़ाई भी है। कभी पढ़-लिखकर जिंदगी बदलने का सपना देखने वाली सपना आज घर की जिम्मेदारियों और तंगहाली के बीच अपना भविष्य अंधेरे में जाता देख रही है। कैमरे के सामने सपना ने आंखों में आंसू भरकर बताया कि घर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि स्कूल की फीस तक जमा नहीं हो सकी। वह बोली, मम्मी अक्सर बीमार

- स्कूल की फीस जमा न करने पर काट दिया गया नाम!
- बीमार मां, कच्चा घर और गरीबी के बोझ तले दब गया पढ़ाई का सपना
- फीस न भर पाने पर छूटी पढ़ाई, जिम्मेदारियों ने थाम ली किताबों की जगह
- 2016 की जांच में पात्र पाए जाने के बाद भी परिवार को नहीं मिला आवास

रहती थीं। इलाज और दवाइयों में ही पैसे खत्म हो जाते थे। पापा मजदूरी करके घर चलाते हैं। फीस भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए स्कूल वालों ने नाम काट दिया। इसके बाद पढ़ाई छूट गई। सपना ने बताया कि उसने आठवीं तक पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद किताबों की जगह घर की

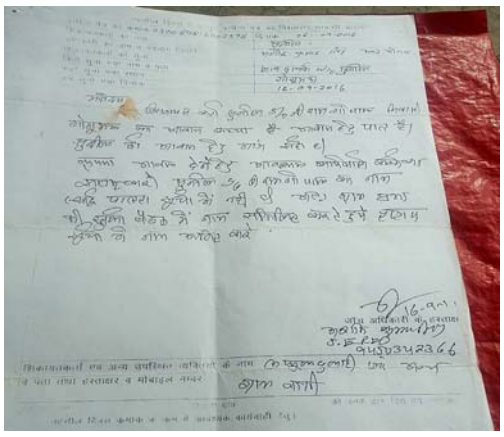

परेशानियों ने ले ली। वह बोली, हम पढ़ना चाहते थे, लेकिन घर की हालत बहुत खराब है। कभी दवा के पैसे नहीं होते, कभी खाने की चिंता रहती है। पापा अकेले कितना करें।

परिवार की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी उनके घर में शौचालय तक नहीं है। सपना ने दर्द भरी आवाज में कहा, खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है। कई बार खेत वाले मना कर देते हैं। बहुत शर्मिंदगी होती है। समझ नहीं आता कि हमारा घर कब बनेगा। मजदूर सुनील कठेरिया रोज दिहाड़ी कर परिवार पालने की कोशिश करते हैं। कभी काम मिल जाए तो घर का चूल्हा जलता है, वरना पूरा परिवार चिंता में डूब जाता है। बड़ी बेटी की शादी भी उन्होंने कर्ज लेकर की थी। अब बीमारी, कर्ज और गरीबी के बीच परिवार जिंदगी से संघर्ष कर रहा है। बेटी की बातें सुनकर पिता सुनील कठेरिया भी भावुक हो गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, साहबज बस बच्चों के सिर पर पक्की छत दिला दो। जिंदगी मजदूरी में निकल गई, लेकिन बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं देख पा रहे। गोगूमऊ गांव का यह परिवार सिर्फ गरीबी की मार नहीं झेल रहा, बल्कि उन सरकारी वादों का दर्द भी सह रहा है, जो वर्षों बाद भी जमीन पर पूरे नहीं हो सके।

2016 की जांच में पात्र मिला था परिवार, फिर भी नहीं मिला आवास

सुनील कठेरिया ने आवास की मांग को लेकर वर्ष 2016 में तहसील समाधान दिवस में शिकायत की थी। शिकायत के बाद अधिकारियों द्वारा की गई जांच में साफ तौर पर माना गया था कि उनका मकान कच्चा है और वह सरकारी आवास योजना के पात्र हैं। जांच आख्या में आवास दिलाने के लिए कार्रवाई की संस्तुति भी की गई थी। इसके बावजूद करीब दस साल बीत जाने के बाद भी परिवार को न आवास मिला और न कोई स्थायी राहत। कागजों में पात्र घोषित होने के बावजूद सुनील कठेरिया आज भी अपने परिवार के साथ जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। इस मामले में एसडीएम बिल्हौर मनीष कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। बीडीओ से वार्ता कर जाँच करवाते हैं।

चौबेपुर में ग्राम प्रधान के पति ने फंदा लगाकर दी जान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बोझा गांव में ग्राम प्रधान के पति ने घर के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अरुण कुमार के रूप में हुई है। वह पेशे से डीसीएम चालक थे और कानपुर के एक व्यापारी की गाड़ी चलाते थे। उनकी पत्नी गांव की ग्राम प्रधान हैं। परिवार में पत्नी के अलावा एक छह वर्षीय बेटा और तीन वर्षीय बेटी हैं।

ग्रामीणों के मुताबिक, अरुण मंगलवार को छुट्टी लेकर घर आए थे। शाम को उनके वाहन मालिक घर पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बाद में फोन पर भी उनकी किसी से बहस हुई थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद घर में भी विवाद हुआ।परिजनों का कहना है कि अरुण शराब पीने के आदी थे और मंगलवार रात भी नशे में थे। देर रात वह कमरे में चले गए। बुधवार तड़के करीब चार बजे उन्होंने कमरे के कुंडे में धोती के सहारे फंदा लगा लिया। पत्नी की नजर पड़ते ही चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अरौल थाने के दरोगा पर युवती ने लगाया छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। अरौल थाना क्षेत्र के ऑकिन गांव की एक युवती ने थाने के दरोगा पर छेड़छाड़, मारपीट, जातिसूचक गालियां देने और रुपये लूटने का आरोप लगाते हुए बिल्हौर एसीपी से शिकायत की है।पीड़िता ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

पीड़िता ने दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 24 मई की शाम करीब छह बजे उसके पिता और ताऊ मकान की छत पर काम कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान अरौल थाने में तैनात दरोगा उसके घर पहुंचा। युवती का आरोप है कि दरोगा ने उसे घर में अकेला पाकर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर जब उसने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की तो दरोगा ने मोबाइल छीन लिया और जातिसूचक गालियां देते हुए थप्पड़ मार दिए।

- एसीपी दफ्तर पहुंच लगाई न्याय की गुहार
- रिपोर्ट लिखाने जाने पर थाने से भगा देने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद दरोगा ने गांव के ही सरमन दिवाकर, सौरभ, शिवानी, मानसी, मीनू समेत अन्य लोगों को बुला लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरा दी और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। युवती ने आरोप लगाया कि घर में लेंटर डालने के लिए रखे 30 हजार रुपये भी अलमारी से निकाल लिए गए। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि सूचना पर पहुंची पुलिस उसके पिता और चाचा को थाने ले जाने के बजाय मकनपुर चौकी ले गई, जहां उनके साथ मारपीट की गई। पीड़िता का कहना है कि जब वह शिकायत दर्ज कराने अरौल थाने पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने उसे थाने से भगा दिया और गांव में नहीं रहने देने की धमकी दी। पीड़िता ने एसीपी बिल्हौर से मेडिकल परीक्षण कराकर रिपोर्ट दर्ज कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

जनगणना कार्य में अव्वल प्रगणक हुए सम्मानित

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। जनगणना के तहत चल रहे मकान सूचीकरण एवं भवन गणना कार्य को शत-प्रतिशत पूरा करने वाले प्रगणकों को मंगलवार को बीआरसी बिल्हौर में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी बिल्हौर मनीष एवं तहसीलदार अनुभव चंद्रा ने प्रगणकों को माल्यार्पण, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया।

सम्मानित होने वालों में प्राथमिक विद्यालय मोहिउद्दीनपुर प्रथम के प्रधानाध्यापक अवनीश कुमार कटियार, उच्च प्राथमिक विद्यालय बैड़ी अलीपुर की सहायक अध्यापिका निहारिका पाल तथा नेहरू इंटर कॉलेज अरौल के प्रवक्ता विवेक पटेल शामिल रहे। इन सभी ने अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में जनगणना के मकान सूचीकरण कार्य को समय से पूरा किया।

- अवनीश कटियार, निहारिका पाल और विवेक पटेल हुए सम्मानित
- बीआरसी परिसर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह

तहसीलदार अनुभव चंद्रा ने कहा कि जनगणना का कार्य बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा होता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर सटीक आंकड़े जुटाना बड़ी चुनौती है।

उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों से अन्य कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस दौरान बीडीओ बिल्हौर,नायब तहसीलदार दिव्या वर्मा, शिक्षक धर्मेंद्र समेत अन्य शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे

हमीरपुर में दो डंपरों की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

» बिवांर थाना क्षेत्र में तड़के हुआ दर्दनाक हादसा, खलासी झुलसा

» मोरम लदे डंपरों की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग

» स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

हमीरपुर। जिले के बिवांर थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के दो डंपरों की भिड़ंत के बाद भीषण आग लगने से एक चालक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।जानकारी के अनुसार घटना बिवांर थाना क्षेत्र के जलालपुर रोड स्थित बंधुर मार्ग पर बिवांर गांव से करीब दो किलोमीटर दूर हुई। बताया गया कि जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी गांव से दो डंपर मोरम

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

लादकर जा रहे थे। इसी दौरान एक डंपर खराब होकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे दूसरे मोरम लदे डंपर ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में अचानक आग लग गई। पीछे से टकराने वाला डंपर देखते ही देखते आग का गोला बन गया। डंपर के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका और उसकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई।

वहीं खलासी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना की सूचना पर बिवांर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने मृत चालक के शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही है।

बेटे संग कुएं में कूदी महिला, दोनों की गई जान

» तालबेहट क्षेत्र के म्याऊं गांव की घटना, मानसिक तनाव की आशंका

» सुबह कुएं में उतराते मिले दोनों शव, पुलिस जांच में जुटी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

झांसी। ललितपुर जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में मां-बेटे की मौत की दर्दनाक घटना सामने आई है। म्याऊं गांव में एक महिला अपने तीन वर्षीय बेटे के साथ कुएं में कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय रानी कुशवाहा सोमवार रात अपने तीन वर्षीय बेटे व्योम के साथ घर से निकली थी। उसने परिजनों से शौच के लिए बाहर जाने की बात कही थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास तलाश की, मगर उसका कोई पता नहीं चला। मंगलवार सुबह गांव के बाहर स्थित एक कुएं में मां-बेटे के शव उतराते दिखाई दिए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।पुलिस के मुताबिक रानी पिछले करीब एक महीने से अपने मायके में रह रही थी। प्रारंभिक जांच में उसके मानसिक तनाव में होने की बात सामने आई है। हालांकि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।तालबेहट कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।

शादी के 14 साल बाद भी संतान न होने के तनाव में दंपत्ति ने दी जान

» खेत पर गए दंपत्ति के शव पेड़ से लटके मिले, गांव में हड़कंप

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

ऐटा। निधौली कलां थाना क्षेत्र के रशीदपुर गांव में संतान न होने के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार गांव निवासी 35 वर्षीय भानु प्रताप सिंह की शादी करीब 14 वर्ष पहले रामा देवी से हुई थी। लंबे समय तक संतान न होने के कारण दोनों काफी परेशान रहते थे। परिजनों ने बताया कि दंपत्ति

मौके पर जांच-पड़ताल करती पुलिस

ने कई जगह इलाज भी कराया था। जांच में रामा देवी की बच्चेदानी में गांठ होने की बात सामने आई थी, जिसके चलते उनका उपचार अलीगढ़ में चल रहा था।

मंगलवार शाम दोनों खेत पर काम करने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे।

काफी तलाश के बाद गांव के बाहर एक पेड़ पर दोनों के शव फांसी के फंदे से लटके मिले। यह दृश्य देखकर परिजनों के होश उड़ गए। घटना की सूचना रात करीब तीन बजे पुलिस को दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएसपी स्वेताभ पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शुरुआती जांच में संतान न होने के कारण मानसिक तनाव की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

बरेली में अपहृत मासूम सकुशल बरामद, मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार

» डेढ़ साल के बच्चे को बेचने की फिराक में थे आरोपी, पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा

» जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल, एक हेड कांस्टेबल भी हुआ जख्मी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बरेली। बरेली में डेढ़ साल के अपहृत बच्चे को बेचने जा रहे दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जबकि फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ है। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। बच्चे को देखते ही उसकी मां फूट-फूटकर रो पड़ी और हाथ जोड़कर पुलिस टीम का धन्यवाद किया।घटना 24 मई की है, जब मनौना धाम क्षेत्र में रहने वाले रमन का डेढ़ वर्षीय बेटा घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया था। काफी तलाश के बाद परिजनों ने आंवला थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दो युवक बच्चे को ले जाते दिखाई दिए। इसके बाद एसपी साउथ अंशिका वर्मा के निर्देशन में पांच टीमें गठित कर तलाश शुरू की गई।

सोमवार देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बच्चे को दिल्ली ले जाकर बेचने की फिराक में हैं। फुलासी तिराहे पर घेराबंदी के दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने लगे। पीछा करने पर बाइक फिसल गई और बच्चा झाड़ियों में जा गिरा। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहजहांपुर निवासी योगेश कन्नौजिया और बदायूं निवासी पवन सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने बच्चों को निसंतान दंपत्तियों को बेचने वाले गिरोह से जुड़े होने की बात कबूली। पुलिस ने उनके पास से दो तमंचे, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जलनिकासी ठप, सड़क पर बह रहा गंदा पानी

» बिल्टी गांव की सीसी सड़क पर जलभराव से ग्रामीण परेशान, बीमारी फैलने का खतरा

» लोक निर्माण विभाग और पंचायत विभाग एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गजनेर-रायपुर मुख्य मार्ग से बिल्टी गांव को जाने वाली सीसी सड़क पर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सड़क के दोनों ओर नालियां बनी होने के बावजूद पानी निकासी का कोई स्थायी साधन नहीं है, जिससे घरों का गंदा और बदबूदार पानी सड़क पर भरकर बह रहा है। जलभराव के कारण राहगीरों और ग्रामीणों का निकलना दूभर हो गया है।ग्रामीणों के अनुसार करीब आठ वर्ष पहले गजनेर-रायपुर मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया गया था। इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से आबादी तक पहुंचने के लिए सीसी सड़क का निर्माण कराया गया।

सड़क किनारे नालियां तो बनाई गईं, लेकिन उनके पानी की निकासी के लिए आगे कोई नाला या अन्य व्यवस्था नहीं की गई। पहले नालियों का पानी मुख्य मार्ग किनारे बनी खाइयों में निकल जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों ने खाइयों को मिट्टी डालकर पाट दिया।

इससे जलनिकासी पूरी तरह बाधित हो गई। अब हालात यह हैं कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा होकर बदबू फैला रहा है। ग्रामीण रामगोपाल, जयनारायण, राजू और शिवराम ने बताया कि मच्छरों और गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। छोटे बच्चे भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

ग्रामीणों ने नाला निर्माण की उठाई मांग

ग्राम प्रधान अंजना सिंह के पति अभिषेक सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क किनारे नाला निर्माण नहीं कराया गया, जबकि अन्य स्थानों पर नाले बनाए गए हैं। जलनिकासी बाधित होने से समस्या गंभीर हो गई है। ग्रामीणों ने जल्द नाला निर्माण कराकर स्थायी समाधान की मांग की है।

सीडीओ साहब! नाली नहीं तो कैसे मिलेगा स्वच्छता का लाभ?

» ग्राम पंचायत मौजमपुर के मजरा सुंदरपुर के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। सरकार गांवों में नाली, खड़ंजा और इंटरलॉकिंग निर्माण के लिए लाखों रुपये खर्च कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के दावे कर रही है, लेकिन विकास खंड रसूलाबाद की ग्राम पंचायत मौजमपुर के मजरा सुंदरपुर की तस्वीर इन दावों की पोल खोल रही है। गांव में न तो समुचित नाली निर्माण कराया गया और न ही गलियों की हालत सुधारी गई, जिससे ग्रामीणों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सुंदरपुर गांव में इसका असर नजर नहीं आता। गांव की गलियां कीचड़ और गंदे पानी से लबालब हैं, जिससे लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बनाई गई सड़कें भी अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं।ग्रामीण रामकृपाल, अखिलेश, गिरजावती, तिलक सिंह और मूलचंद्र ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान भारी लापरवाही बरती गई थी। सड़क तो बना दी गई, लेकिन जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं कराया गया। इसके चलते सीवर टैंकों और घरों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। पुरानी नालियां भी टूटकर ध्वस्त हो चुकी हैं, जिनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गांव में जगह-जगह जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। बरसात से पहले ही हालात बदतर हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गांव की सड़कों पर फैले गंदे पानी और जलभराव से सड़ांध फैलने लगी है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नाली निर्माण, सड़क मरम्मत और जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि गांववासियों को राहत मिल सके।

इंटरलॉकिंग सड़क पर गिरता पानी

लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार पैर में लगी गोली

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र में महिला से कान का बाला लूट कर फरार हुए बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, लूटा गया बाला और बिना नंबर की बाइक बरामद की है।हरदियानाला गांव में 24 मई को उपले पाथ रही महिला से दो बाइक सवार बदमाशों ने रामजानकी मंदिर का पता पूछने के बहाने कान का बाला लूट लिया था। मामले में पीड़िता के पुत्र आशीष की तहरीर पर शिवली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस पहले ही एक आरोपी इस्माइल निवासी जल्लापुर सिकंदरा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, जबकि दूसरा आरोपी राहुल सिंह निवासी ब्रह्मनगर कंजड डेरा थाना अकबरपुर फरार था। बुधवार देर रात शिवली पुलिस केशरी निवादा-रामपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस के रोकने पर उसने भागने का प्रयास किया। बाइक फिसलने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर सीएचसी शिवली भेजा। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, लूटा गया पीबाला और बिना नंबर की पल्सर बाइक बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ विभिन्न जिलों में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट समेत डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

सरकार के फैसले से प्रधानों में उत्साह

प्रधान संघ के ब्लाक अध्यक्ष अर्जुन सिंह का हुआ सम्मान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद ब्लाक परिसर में प्रधान संघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में प्रधानों की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें ग्राम प्रधानों को चुनाव तक प्रशासक नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया गया। सभी प्रधानों ने ग्राम प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन सिंह का फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बधाई दी। अर्जुन सिंह गौर ने सभी प्रधानों के साथ मिलकर जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ तक प्रशासक बनाए जाने की मांग को लेकर संघर्ष किया था।

जिसका असर भी देखने को मिला। अर्जुन सिंह ने कहा कि प्रधानों के संगठनों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। वहीं सरकार के द्वारा प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने पर लंबित पड़े विकास कार्य पूरे होंगे और आगे विकास कार्यों में तेजी आएगी। उसरी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरगोविंद सिंह नेता ने कहा कि प्रधानों को ही जिम्मेदारी मिलने पर विकास कार्य नहीं रुकेंगे और प्रधानों को अब और समय मिलने से अन्य कार्यों को भी जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से गोविंद सिंह,मानवेंद्र पाल, जैलसिंह राठौर,प्रदीप यादव, अजय यादव, सुनील यादव, लालमन दिवाकर,उदय प्रताप सिंह,अनिल कुमार सहित कई प्रधान मौजूद रहे।

तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर, पांच घायल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर थाना क्षेत्र के किशुनपुर गांव मोड़ पर मंगलवार दोपहर तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार पांच लोग घायल हो गए। इनमें तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।कथरी गांव निवासी संदीप ने पुलिस को बताया कि ऑटो से शाहजहांपुर बाजार खरीदारी करने जा रहा था। किशुनपुर गांव मोड़ के पास सट्टी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने सामने से ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो सड़क किनारे पलट गया। हादसे में जरी गांव निवासी कल्याण सिंह, तेजनारायण, कदौरा कालपी निवासी कादिर, ऑटो चालक खरका गांव निवासी तेजपाल समेत संदीप घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर राहगीरों ने सरकारी एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को राजपुर पीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद संदीप, कल्याण सिंह और तेजनारायण की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया है।

देहात संक्षिप्त.....

रास्ते में रोककर युवक पर हमला, मामला दर्ज

कानपुर देहात। पीड़ित धर्मपाल ने भोगनीपुर कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि बीती 23 मई को वह पुखरायां से अपने घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही लवलेश पुत्र सिपाहीलाल ने उसे रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने सरिया से हमला कर दिया, जिससे धर्मपाल के सिर में गंभीर चोट लग गई और खून बहने लगा। आसपास मवेशी चरा रहे लोगों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। भोगनीपुर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डिवाइडर से टकराई युवक घायल

कानपुर देहात। कालपी निवासी विकास बाइक से भोगनीपुर की ओर आ रहा था। जैसे ही वह चौरा गांव के पास पहुंचा, तभी अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि वह बाइक से गिरकर घायल हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे निजी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा घायल युवक का उपचार किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मामले की जानकारी जुटाई।

भट्ठा मजदूर ने आत्महत्या का किया प्रयास

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक भट्टे पर काम करने वाले मजदूर झांसी के मऊरानीपुर निवासी संजय (55) ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने उसे फंदे से उतारकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

नोनपुर गांव के पास दो बाइकों की भिड़ंत, तीन घायल

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के नोनपुर गांव के समीप दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घाटमपुर निवासी विकास और सुनील बाइक से पुखरायां की ओर जा रहे थे, जबकि घाटमपुर निवासी महेश बाइक से भोगनीपुर की ओर से घाटमपुर जा रहा था। नोनपुर गांव के पास पहुंचते ही दोनों बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई।

पॉक्सो मुकदमे के बाद भी गिरफ्त से दूर आरोपी, गंगा ढाबा पर उठे सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रनिया का गंगा ढाबा बना अनैतिक कार्यों का अड्डा !

आरोपी आशीष यादव

कानपुर देहात। रनिया थाना क्षेत्र स्थित चर्चित गंगा ढाबा एक बार फिर गंभीर आरोपों के चलते चर्चा में है। ढाबा संचालक आशीष यादव के खिलाफ नाबालिग युवती से जुड़े मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

जानकारी के अनुसार, 04 अप्रैल 2026 को हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के 52 दिन बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी को संरक्षण मिलने के कारण अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि ढाबा का संचालन लगातार जारी है, जबकि मामला बेहद गंभीर धाराओं से जुड़ा हुआ है। मामले में गंगा ढाबा का नाम सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ढाबा पर अब तक कोई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

इधर, मामले से जुड़े कथित समझौता पत्र और लेन-देन के दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। हालांकि वायरल दस्तावेजों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है। पीड़ित परिवार ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी, गंगा ढाबा पर सख्त कार्रवाई और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब पूरे मामले में लोगों की नजर पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

पब्लिक को बवाल करने दो, पुलिस मत पहुंचना दूर खड़े होकर देखो

» सीओ अकबरपुर के कथित वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

» एसपी देहात ने मांगा स्पष्टीकरण, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

सीओ संजय सिंह

कानपुर देहात। अकबरपुर कोतवाली में आयोजित पीस कमेटी की बैठक का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। वायरल वीडियो में सीओ अकबरपुर संजय सिंह कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि पब्लिक को बवाल करने दो, पुलिस मत पहुंचना और दूर खड़े होकर देखो, तभी सुधरेगी जनता। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में सीओ द्वारा कथित रूप से यह भी कहा गया कि कुछ होगा तो हम बचा लेंगे, जैसे पहले भी बचाया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किन मामलों में बचाने की बात कही जा रही थी। वायरल वीडियो में कुछ दिन पहले हुए अमूल वाहन चालक अनुराग तिवारी मारपीट प्रकरण का भी जिक्र बताया जा रहा है। आरोप है कि उस मामले में चौकी इंचार्ज द्वारा युवक के साथ अभद्रता और मारपीट की गई थी। वीडियो में सीओ के कथित बयान को लेकर पुलिस विभाग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं।त्योहारों के मौसम से पहले इस प्रकार का वीडियो सामने आने से आम लोगों में चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि विवाद की स्थिति में पुलिस मौके पर नहीं पहुंचेगी तो कानून व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी। मामले पर एसपी देहात ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो का संज्ञान लिया गया है। संबंधित अधिकारी को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जांच के आधार पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

भीषण गर्मी में शोपीस बने वाटर कूलर, ग्रामीणों को नहीं मिल रही राहत

» लाखों रुपये के उपकरण देखरेख के अभाव में बेकार हो गए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। क्षेत्र पंचायत निधि से ग्राम पंचायतों में लगाए गए वाटर कूलर भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के बजाय शोपीस बने हुए हैं। तेज धूप और बढ़ती गर्मी में जहां ग्रामीणों को ठंडा पेयजल मिलना चाहिए, वहीं अधिकांश गांवों में वाटर कूलर खराब पड़े होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में लगे वाटर कूलरों की स्थिति बदहाल बनी हुई है। लाखों रुपये खर्च कर लगाए गए ये उपकरण देखरेख के अभाव में बेकार साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं हैं। क्षेत्र की भीतरगांव ग्राम पंचायत के मजरा भग्गा निवादा में लगा वाटर कूलर लंबे समय से खराब पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में सबसे अधिक परेशानी राहगीरों और आम लोगों को हो रही है। ग्राम प्रधान जयचंद्र सिंह ने अपने स्तर से एक बार वाटर कूलर को सही भी कराया था, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर खराब हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि विकास खंड प्रशासन की ओर से रखरखाव की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई गई है। वहीं ग्राम प्रधानों का कहना है कि मरम्मत और रखरखाव के लिए अलग से कोई बजट या मद उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। भीषण गर्मी में खराब पड़े वाटर कूलरों को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों ने मांग की है कि सभी खराब वाटर कूलरों को जल्द दुरुस्त कराया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। इस

संबंध में सचिव अविनाश शुक्ला ने बताया कि खराब वाटर कूलर की शिकायत मिली है और उसे जल्द सही कराया जाएगा।

ईवीएम वेयरहाउस का डीएम ने किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त निर्देश

» राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत ईवीएम की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कपिल सिंह ने बुधवार को ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, रखरखाव और सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता का गहनता से परीक्षण किया।

डीएम कपिल सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही वेयरहाउस में स्थापित तकनीकी उपकरणों, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा प्रबंधों को नियमित रूप से अपडेट रखने पर जोर दिया। उन्होंने परिसर की स्वच्छता और चौबीस घंटे निगरानी व्यवस्था बनाए रखने की भी हिदायत दी।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमित कुमार तथा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी गिरवर प्रसाद मौजूद रहे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भाजपा से श्यामू शुक्ला, समाजवादी पार्टी से शेखू खान, कांग्रेस से गोविंद यादव और भारतीय समाजवादी पार्टी से आशुतोष गौतम सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी निरीक्षण में शामिल हुए। मौके पर सुरक्षा कर्मी और निर्वाचन विभाग के कर्मचारी भी तैनात रहे।

2027 मिशन से पहले यूपी बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक सर्जिकल स्ट्राइक, आधे पदाधिकारी बदलने की तैयारी

क्षेत्रीय अध्यक्षों से लेकर मोर्चों तक नए चेहरों पर दांव, बूथ मैनेजमेंट और सामाजिक समीकरण साधने पर फोकस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी संगठन में करीब 50 प्रतिशत तक फेरबदल किया जा सकता है। इसके तहत सभी छह क्षेत्रीय इकाइयों के अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा है, जबकि राज्य कार्यकारिणी और विभिन्न मोर्चों में भी व्यापक परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि बीजेपी के सातों मोर्चों को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। पार्टी नेतृत्व इस बार संगठन में युवा और सक्रिय चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। लंबे समय से एक ही पद पर जमे नेताओं की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश संगठन की विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा सौंप दी गई है। इसके बाद संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के बीच अहम बैठक भी हुई, जिसमें आगामी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

पार्टी का फोकस बूथ स्तर को और मजबूत करने पर है। बीजेपी नेतृत्व मानता है कि 2027 के चुनाव में मजबूत बूथ प्रबंधन और सामाजिक समीकरण निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले का जवाब देने के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब संगठन में बदलाव की प्रक्रिया तेज होगी। पुराने क्षेत्रीय अध्यक्षों को राज्य इकाई में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि नए क्षेत्रीय अध्यक्षों को अपनी टीम चुनने की छूट मिलेगी। बीजेपी लंबे समय से चल रही संगठनात्मक बदलाव की चर्चाओं को अब अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है।

नेपाल सीमा से भारत में घुसते ही एटीएम वैन लूटकांड के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार

» दोनों के खिलाफ गाजियाबाद के थाना क्रासिंग रिपब्लिक में इस मामले में मुकदमा दर्ज है

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। एसपी डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन बॉर्डर चेकिंग अभियान के दौरान सम्पूर्णानगर पुलिस ने गाजियाबाद एटीएम वैन लूटकांड के दो वांछित इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी नेपाल भाग गए थे और भारत लौटते समय पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुहैब और फिरोज के रूप में हुई है, जिन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के बचे हुए एक लाख रुपये नकद, दो देशी तमंचे 12 बोर, पांच जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।

पुलिस के मुताबिक 25 मई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गाजियाबाद एटीएम वैन लूटकांड के आरोपी नेपाल से वापस भारत आने वाले हैं। सूचना मिलते ही सम्पूर्णानगर पुलिस ने गोविन्द नगर चौराहा क्षेत्र और नेपाल सीमा से जुड़े मार्गों पर सघन चेकिंग शुरू कर दी।

कुछ देर बाद दो संदिग्ध युवक नेपाल की ओर से पैदल आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने 6 मई 2026 को गाजियाबाद हाईवे पर एटीएम वैन लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट में कुल 25 लाख रुपये मिले थे, जिसमें से ढाई लाख रुपये दोनों के हिस्से में आए थे। आरोपी नेपाल में छिपे हुए थे और बकरीद मनाने अपने घर लौट रहे थे। गौरतलब है कि गाजियाबाद के थाना क्रासिंग रिपब्लिक में इस मामले में मुकदमा दर्ज है और दोनों आरोपियों की तलाश लंबे समय से की जा रही थी।

अब एक दिन में बनेगा जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र, यूपी में शुरू होगा 'वन डे गवर्नेंस'

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने या घर-जमीन के दाखिल-खारिज जैसे कामों के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निगमों में 'वन डे गवर्नेंस सेंटर' शुरू करने का फैसला किया है, जहां आम नागरिकों के कई जरूरी काम एक ही दिन में पूरे किए जाएंगे।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इस नई व्यवस्था का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार नगर निकायों की सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रही है।

फिलहाल लखनऊ में यह सेंटर तैयार हो चुका है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में भी इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है।मंत्री ने बताया कि इस मॉडल का उद्देश्य लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली भाग-दौड़ और देरी से राहत देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वन डे गवर्नेंस सिस्टम लागू किया था और अब उसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना है। शर्मा ने दावा किया कि सामान्य मामलों में लोगों को आधे घंटे के भीतर प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा, जबकि जटिल मामलों में भी उसी दिन समाधान देने का प्रयास होगा।उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगी, जो ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते।लखनऊ नगर निगम में तैयार किए गए सेंटर में वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की विशेष व्यवस्था, चाय-पानी समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।यह घोषणा लखनऊ महापौर के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहरी विकास, स्मार्ट सिटी और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा हुई।ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के शहरों को वैश्विक स्तर की सुविधाओं से लैस करना है।

11 साल पहले 'मरा' दिखाया आरोपी निकला जिंदा, विजिलेंस में हड़कंप

» आगरा में भ्रष्टाचार केस की जांच करने वाले तत्कालीन विवेचक पर दर्ज हुआ मुकदमा

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

आगरा। आगरा में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़े एक पुराने मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपी को 11 साल पहले सरकारी कागजों में मृत दिखा दिया गया था, लेकिन जांच में वह जिंदा मिला। इस खुलासे के बाद विजिलेंस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले में तत्कालीन विवेचक रहे सेवानिवृत्त निरीक्षक अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामला फव्वारा बाजार कोतवाली क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2006 में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनाने की शिकायत सामने आई थी। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने पर मामला शासन तक पहुंचा और विजिलेंस जांच बैठाई गई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर विजिलेंस के तत्कालीन निरीक्षक योगेंद्र सिंह मलिक ने नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों समेत 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इनमें नूरी दरवाजा निवासी देवेंद्र अग्रवाल भी आरोपी बनाए गए थे।

मामले की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक अभय सिंह को सौंपी गई थी। आरोप है कि विवेचक ने केवल अमीन की रिपोर्ट के आधार पर बिना पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और बिना किसी गवाह के बयान दर्ज किए देवेंद्र अग्रवाल को कागजों में मृत दर्शा दिया। इसके बाद वर्ष 2015 में शासन को रिपोर्ट भेज दी गई। हालांकि शासन से इस रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिली और जांच जारी रही।

करीब दो वर्ष पहले विजिलेंस को सूचना मिली कि आरोपी देवेंद्र अग्रवाल जीवित है। जांच में यह तथ्य सही पाए जाने के बाद विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। इसके बाद विजिलेंस निरीक्षक धर्मवीर सिंह की ओर से तत्कालीन विवेचक अभय सिंह के खिलाफ धारा 166-ए समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया। विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अभय सिंह ने विवेचना में गंभीर लापरवाही बरती, अहम साक्ष्य संकलित नहीं किए और मामले को वर्षों तक लटकाए रखा। विभाग का कहना है कि यह कृत्य आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में आता है।बताया गया कि अभय सिंह वर्ष 2017 में विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अब इस मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं आरोपी देवेंद्र अग्रवाल के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि विवेचना में बरती गई लापरवाही के आधार पर तत्कालीन विवेचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की आगे जांच की जा रही है।

दो सौ मीटर में ढेर हो गया सपा सांसद का जन आंदोलन!

सपा सांसद के 'मैनेज प्रदर्शन' ने सपाइयों को किया शर्मिंदा, मंच पर क्रांति, बैरिकेडिंग पर समर्पण!

समीर शाही/ स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। महंगाई, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जिला मुख्यालय घेरने निकले समाजवादी पार्टी के आंदोलन का अंत उस तरह हुआ, जैसे बिना बारूद के पटाखा आवाज बहुत, असर शून्य। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में प्रस्तावित विशाल प्रदर्शन महज दो सौ मीटर में ही दम तोड़ गया। सांसद आवास से निकला काफिला रामपथ पर बैरिकेडिंग तक पहुंचा जरूर, लेकिन वहां जो हुआ उसने सपाइयों को भीतर तक झकझोर दिया।

सैकड़ों कार्यकर्ता जोश में थे। पूर्व विधायक पवन पांडेय, रुश्दी मियां और फिरोज खान गब्बर के नेतृत्व में सपाई बैरिकेडिंग तक पहुंचे। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, नारे गूंजने लगे, माहौल गरमा गया।

लेकिन तभी कहानी में राजनीतिक ट्विस्ट आ गया। बताया जा रहा है कि सांसद अवधेश प्रसाद बैरिकेडिंग तक पहुंचे ही नहीं।

उससे पहले ही प्रशासन के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंप दिया गया और आंदोलन की शांतिपूर्ण अंत्येष्टि कर दी गई।

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसकी भनक तक नहीं लगी।

धरना जिला मुयालय का, सभा सांसद आवास में!

जिस आंदोलन को जिला मुख्यालय तक पहुंचना था, वह महाराणा प्रताप वार्ड और सरदार भगत सिंह वार्ड की सीमाओं में ही कैद होकर रह गया। सभा भी सड़क पर नहीं, सांसद आवास परिसर में निपटा दी गई। अब सवाल उठ रहा है क्या यह आंदोलन था या प्रशासन से पहले से तय औपचारिक कार्यक्रम%? प्रशासन और राजनीति की 'सेटिंग' पर सपा के अंदर ही अब यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो आंदोलन विशाल प्रदर्शन बताया जा रहा था, वह बैरिकेडिंग के आगे पहुंचने से पहले ही ठंडा पड़ गया? कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि जब जनता के मुद्दों पर संघर्ष का दावा किया गया था, तो फिर प्रशासन को बीच रास्ते में ज्ञापन देकर वापसी क्यों कर ली गई? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आंदोलन से ज्यादा मैसेज मैनेजमेंट पर ध्यान था। फोटो खिंच गई, प्रेस नोट जारी हो गया, और संघर्ष का अध्याय खत्म!

सपाइयों में मायूसी, जनता में सवाल

सपा समर्थकों का उत्साह उस समय ठंडा पड़ गया जब उन्हें पता चला कि नेतृत्व बिना संघर्ष किए ही लौट चुका है। कई कार्यकर्ताओं ने इसे 卐आंदोलन की हत्या卐 तक बताया। अब जनता पूछ रही है अगर विपक्ष सड़क पर उतरकर भी सड़क पार नहीं कर पा रहा, तो फिर सरकार को चुनौती कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल क्या अयोध्या में आंदोलन भी अब पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के तहत होने लगे हैं?

एक करोड़ की रेत सरयू में दफन!

» न पंचवटी द्वीप तैयार, न श्रद्धालुओं की आवाजाही फिर किसके लिए बना पीपे का पुल?

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में विकास के नाम पर करोड़ों रुपये किस तरह रेत में बहाए जा रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण जमथरा से निलयम पंचवटी द्वीप तक बनाया गया पीपे का पुल बन गया है। लगभग 200 मीटर लंबे इस अस्थायी पुल पर लोक निर्माण विभाग ने करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन जिस पंचवटी द्वीप परियोजना के लिए इसे बनाया गया, वह आज तक पूरी नहीं हो सकी।

स्थिति यह है कि सरयू नदी में पानी न के बराबर है, चारों तरफ सिर्फ उड़ती रेत दिखाई दे रही है और पुल श्रद्धालुओं की बजाय सवालों का बोझ ढो रहा है। अब विभाग 15 जून से 15 अक्टूबर तक पुल हटाने की तैयारी में है, क्योंकि बरसात में नदी में पानी बढ़ जाता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि गुप्तारघाट से नयाघाट तक वर्षों से सरयू का जलस्तर घटा रहता है और किसान नदी की जमीन पर खेती करने लगते हैं। ऐसे में करोड़ों खर्च कर पीपे का पुल बनाना आखिर किस योजना और जरूरत का हिस्सा था? सवाल यह भी है कि जब पंचवटी द्वीप तैयार ही नहीं था, तो इतनी जल्दबाजी में पुल निर्माण क्यों कराया गया?

नगर वासियों के बकाया करों के ब्याज के माफ होने की आस जगी

» महापौर की मांग पर वीडियो कांफ्रेंसिंग में नगर विकास मंत्री ने किया वादा

» छूट के साथ एक अगस्त से लागू होगी एक मुश्त समाधान योजना

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। बकाया गृह, जलकर एवं सीवेज कर पर ब्याज माफ होने की आस संजोए नगर वासियों के लिए अच्छी खबर है। बकाया करों के ब्याज के माफ होने की आस जग गई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में नगर विकास मंत्री ने महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी से वादा किया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग में महापौर ने मंत्री के सामने बकाया ब्याज माफ करने का मुद्दा तार्किक ढंग से उठाया।

उन्होंने बताया कि प्रक्रियागत खामियों के कारण अधिकांश लोगों तक बकाया टैक्स का बिल समय से नहीं पहुंच सका। इससे भी लोगों को टैक्स जमा करने में विलंब हुआ। उन्होंने नगर विकास मंत्री के सामने वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ सभी लोगों को देने का सुझाव दिया, जिस पर मंत्री ने 50 हजार रुपये की धनराशि को घटाकर सभी बकाएदारों पर लागू करने की बात सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की और एक अगस्त से लागू किए जाने का भरोसा दिया।

लता चौक पर दौड़ता ऑटो बना आग का गोला

» चीख-पुकार के बीच यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी के बेहद व्यस्त लता मंगेशकर चौक पर बुधवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब चलते सीएनजी ऑटो रिक्शा में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ऑटो धू-धू कर जलने लगा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

ऑटो में चालक समेत पांच यात्री सवार थे। आग की लपटें उठते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और सभी ने जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूदकर खुद को सुरक्षित किया। गनीमत रही कि इस भयावह हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।

काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आग कुछ देर बाद लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है।

श्रद्धालुओं की कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बची चार जिंदगियां

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार मंगलवार शाम रुदौली कोतवाली क्षेत्र के एनएच-27 स्थित रौजागांव ओवरब्रिज पर अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते चलती कार धू-धू कर जलने लगी, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। कार में चालक समेत चार लोग सवार थे, जिन्होंने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वाहन सीएनजी कार थी, हालांकि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।

खनन माफियाओं के हौसले बुलंद

शिकायतकर्ता को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश

» महावा गांव में अवैध खनन का विरोध पड़ा भारी, जानलेवा हमले की तहरीर के बाद पुलिस एक्शन में

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। महावा गांव में चल रहे अवैध खनन का मामला अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। खनन की शिकायत करने वाले अजीत प्रताप सिंह को कथित तौर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई।

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने पूराकलंदर थाने में नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले, धमकी और गाली-गलौज की लिखित तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

अजीत प्रताप सिंह का आरोप है कि जब वह शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे, तभी एक ट्रैक्टर चालक और उसके साथ मौजूद लोगों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया।

विरोध करने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि इस मामले में पहले ही 7 ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक जेसीबी सीज की जा चुकी है। वहीं उपजिलाधिकारी सोहावल सविता देवी ने खनन विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अवैध खनन के पीछे किसका संरक्षण है, जो शिकायतकर्ताओं तक को कुचलने की कोशिश की जा रही है।

राम मंदिर में पास की अनिवार्यता खत्म

» भीषण गर्मी के बीच ट्रस्ट ने दी बड़ी राहत, बिना पास भक्त कर रहे दर्शन

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

रामनगरी अयोध्या पहुंचे देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ी राहत दी है। वर्तमान में राम मंदिर परिसर के भीतर स्थित सभी पूरक मंदिरों और सप्तर्षि मंदिरों में दर्शन के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब श्रद्धालु बिना किसी विशेष अनुमति के रामलला दरबार के साथ परिसर में बने अन्य मंदिरों के भी सुगमता से दर्शन कर रहे हैं।ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि भीषण गर्मी और लू के चलते श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम है, इसलिए फिलहाल खुली व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही दर्शनार्थियों की संख्या एक लाख प्रतिदिन से अधिक होगी, पुरानी पास व्यवस्था फिर से लागू कर दी जाएगी। वर्तमान में श्रद्धालुओं को अलग-अलग प्रवेश और निकासी मार्गों से भेजा जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण सुचारू बना रहे। राम मंदिर परिसर में भक्तों के बीच इस नई व्यवस्था को लेकर काफी उत्साह और संतोष देखने को मिल रहा है।

इजरायल का दावा: हमास का नया सैन्य कमांडर एयरस्ट्राइक में ढेर

गाजा सिटी के रिमल इलाके में बहुमंजिला इमारत पर हुआ हमला

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। गाजा पट्टी में जारी युद्ध के बीच इजरायल ने हमास को बड़ा झटका देने का दावा करते हुए उसके नए सैन्य कमांडर मोहम्मद ओदेह को हवाई हमले में मार गिराने की घोषणा की है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्ज ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ओदेह हमास की सैन्य शाखा इज्ज अद-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख था और 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमलों की साजिश में उसकी अहम भूमिका थी।

इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी गाजा सिटी के रिमल इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया। बताया गया कि हमला बेहद सटीक था और इमारत की ऊपरी मंजिल पूरी तरह तबाह हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस हमले में तीन लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि हमास ने अभी तक मोहम्मद ओदेह की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

जानकारी के अनुसार मोहम्मद ओदेह ने 18 मई 2026 को ही हमास की सैन्य शाखा की कमान संभाली थी। उससे पहले इस पद पर मौजूद इज्ज अल-दीन को 15 मई को इजरायली हमले में मार गिराया गया था। ऐसे में महज एक सप्ताह के भीतर हमास के दूसरे शीर्ष सैन्य कमांडर के मारे जाने का दावा संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ओदेह लंबे समय तक हमास के सैन्य खुफिया विभाग का प्रमुख रहा। उस पर आरोप है कि उसने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से पहले इजरायली सैन्य ठिकानों और सीमा सुरक्षा व्यवस्था की संवेदनशील जानकारी जुटाई थी। इसी रणनीतिक तैयारी के आधार पर हमास के लड़ाके इजरायल में घुसपैठ करने में सफल हुए थे। बताया जाता है कि ओदेह हमास के सबसे अनुभवी सुरक्षा ऑपरेटरों में शामिल था। अपने शुरुआती दौर में वह संगठन के आंतरिक सुरक्षा नेटवर्क में सक्रिय रहा और कथित इजरायली मुखबिरों की पहचान कर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संभालता था। बाद में वह हमास के खुफिया विंग का प्रमुख बना और शीर्ष सैन्य नेतृत्व में शामिल हो गया।

➪ इजरायल ने 7 अक्टूबर हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया

इजरायल लंबे समय से उसकी तलाश कर रहा था। वर्ष 2025 में गाजा में उसके पैतृक घर पर हुए हमले में उसका बेटा अम्र मारा गया था, लेकिन उस समय ओदेह बच निकला था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार लक्षित हमलों के बाद ओदेह हमास की उच्च सैन्य परिषद के बचे हुए आखिरी बड़े नेताओं में शामिल था। उसके मारे जाने से हमास की सैन्य रणनीति और कमांड ढांचे पर गंभीर असर पड़ सकता है।

क्यों अहम था मोहम्मद ओदेह?

- हमास की सैन्य खुफिया रणनीति का प्रमुख चेहरा
- 7 अक्टूबर हमले की योजना से जुड़ा नाम
- गाजा में सुरंग नेटवर्क और सुरक्षा ढांचे की गहरी जानकारी
- शीर्ष नेतृत्व के खत्म होने के बाद तेजी से उभरा कमांडर

इजरायल की 'टारगेटेड किलिंग' रणनीति

- इजरायल लगातार हमास नेतृत्व को निशाना बना रहा
- ड्रोन, सैटेलाइट और मानव खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल
- उद्देश्य- हमास की कमांड चेन को कमजोर करना
- इससे संगठन के अंदर नेतृत्व संकट गहराने की आशंका

हर टूटा रिश्ता दुष्कर्म नहीं हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल विवाह का वादा कर लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंध को हर मामले में दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि शुरुआत से ही धोखा देने की मंशा साबित न हो, तो बाद में विवाह से इनकार करना झूठे विवाह वादे पर दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा।न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने यह फैसला कपिल सोम और एक अन्य की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर सुनाया। कोर्ट ने मुरादाबाद की विशेष एससी/एसटी अदालत द्वारा पारित संज्ञान और समन आदेश को रद्द करते हुए पूरे मुकदमे की कार्यवाही निरस्त कर दी।

मामले में महिला ने आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम पर संपर्क के बाद आरोपी कपिल सोम ने विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का आरोप था कि बाद में आरोपी और उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट, जातिसूचक टिप्पणी और आर्थिक शोषण किया। उसने आरोपी के पिता पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसी आधार पर वर्ष 2025 में एससी/एसटी एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि झूठे विवाह वादे और बाद में विवाह टूटने की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। अदालत ने कहा कि दुष्कर्म का मामला तभी बनता है, जब यह साबित हो कि आरोपी ने शुरुआत से ही विवाह करने का कोई इरादा नहीं रखा था और केवल शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से झूठा वादा किया गया था।कोर्ट ने पाया कि महिला 24 वर्ष की बालिग और शिक्षित थी। वह अपनी इच्छा से आरोपी के संपर्क में आई, उसके साथ मेरठ गई और लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह रही। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से संबंध सहमति आधारित प्रतीत होते हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे साबित हो कि शुरुआत से ही आरोपी की मंशा धोखा देने की थी।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि लंबे समय तक बिना विरोध चले संबंधों में बाद में आपराधिक आरोप लगाने से हर असफल प्रेम संबंध को आपराधिक मुकदमे में बदला जा सकता है, जिससे न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। अदालत ने कहा कि हर असफल रिश्ता दुष्कर्म का मामला नहीं हो सकता।कोर्ट ने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 इस मामले में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि कथित घटनाएं वर्ष 2022-23 की थीं, जबकि बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता।एससी/एसटी एक्ट के आरोपों पर अदालत ने कहा कि एफआईआर और बयानों में सार्वजनिक रूप से जातिसूचक अपमान के स्पष्ट आरोप नहीं हैं। केवल जाति का उल्लेख करते हुए विवाह से इनकार करना एससी/एसटी एक्ट की धाराओं को स्वत: लागू नहीं करता। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसके साथ ही अदालत ने 5 जुलाई 2025 के समन आदेश और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

क्यूबा पर दोहरी मार: आर्थिक तबाही के बीच ट्रंप की चेतावनी से बढ़ी वैश्विक चिंता

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। अमेरिका से महज 90 मील दूर स्थित क्यूबा इस समय गंभीर आर्थिक, ऊर्जा और कूटनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कभी शीत युद्ध के दौर में अमेरिका को खुली चुनौती देने वाला यह कैरेबियाई देश आज बिजली कटौती, ईंधन संकट और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि क्यूबा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है।

देशभर में लंबे ब्लैकआउट आम हो चुके हैं। कई इलाकों में घंटों बिजली नहीं मिल रही, जिसके कारण उद्योग-धंधे प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल और जरूरी सेवाएं जनरेटर के सहारे चल रही हैं। खाद्य सामग्री और दवाओं की कमी ने आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार खराब होती अर्थव्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं।

क्यूबा का इतिहास बताता है कि यह देश कभी लैटिन अमेरिका में अमेरिका विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। 1959 की क्रांति में फिदेल कास्त्रो और चे गेवेरा ने अमेरिकी समर्थित फुल्गेंसियो बतिस्ता सरकार को हटाकर कम्युनिस्ट शासन स्थापित किया था। इसके बाद 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार तक ले गया था। उस समय सोवियत संघ का मजबूत समर्थन क्यूबा की सबसे बड़ी ताकत था।

हालांकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। तेल, खाद्यान्न और वित्तीय सहायता बंद होने से देश में गहरा संकट पैदा हुआ। इस दौर को 'स्पेशल पीरियड' कहा गया, जब लाखों क्यूबाई नागरिक बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका की ओर पलायन करने लगे।

अब एक बार फिर क्यूबा अंतरराष्ट्रीय दबाव में घिरा दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। 1996 में अमेरिकी विमानों को मार गिराने की घटना को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर कार्रवाई की चर्चाएं भी तेज हैं। माना जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज पारिला ने वैश्विक समुदाय से मदद की अपील करते हुए कहा कि देश मानवीय संकट के दौर से गुजर रहा है और दुनिया को क्यूबा के साथ खड़ा होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में क्यूबा पहले की तरह सामरिक रूप से मजबूत नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com